सं. ए-45011/4/2021-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

***

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2021

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को सितम्बर, 2021 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश के अवर्गीकृत भाग को इसके साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

अरूप श्याम

(अरूप श्याम चौधुरी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष नं. 23095091

प्रति

1. केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
6. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
7. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
8. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली के सभी सदस्य।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. वित्त राज्य मंत्री के प्रधान सचिव, वित्त सचिव के पीपीएस, सचिव (आ.का.) के पीपीएस, सचिव (राजस्व) के पीपीएस, सचिव (व्यय) के पीपीएस, सचिव (दीपम) के पीपीएस।
11. मुख्य आर्थिक सलाहकार, आ.का.वि.।
12. अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
13. सुश्री मीरा स्वरूप, विशेष सचिव।
14. श्री ए.एम. बजाज, अपर सचिव (एफएम), आ.का.वि.
15. श्री रजत कुमार मिश्रा, अपर सचिव (बजट), आ.का.वि.।
16. श्री संजीव सान्याल, प्रधान आर्थिक सलाहकार, आ.का.वि.
17. आर्थिक कार्य विभाग के सभी प्रभागाध्यक्ष।
    वरिष्ठ सलाहकार (सीएण्डसी/एफएसएलआर/एफएस और सीएस)/ संयुक्त सचिव (बीसी और आईईआर)/ संयुक्त सचिव (निवेश)/ सलाहकार (आईईआर) सीएएए।
18. श्री राजेश मल्होत्रा, महानिदेशक (एम और सी), वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

सं. ए-45011/4/2021-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

***

विषयः सितंबर, 2021 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश।

1. वृहत् आर्थिक सिंहावलोकन

राजकोषीय समेकन उपायों और संरचनात्मक सुधारों के बल पर भारत के व्यापक आर्थिक मूल तत्व मजबूत बने हुए हैं। कृषि क्षेत्र लगातार मजबूत हो रहा है। विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों में तेज उछाल ने उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक मजबूती का प्रदर्शन करने वाले विकास चालकों के रूप में मजबूती से स्थापित किया है। जबकि संपर्क-गहन सेवा क्षेत्र में पुनरुद्धार धीरे-धीरे बना हुआ है, तेजी से टीकाकरण और तनावग्रस्त क्षेत्रों के लिए सरकार के लक्षित राहत उपायों के कारण इसमे गति आएगी।

जुलाई, अगस्त और सितंबर में कई प्रमुख वृहत आर्थिक संकेतकों में एक व्यापक आधारित रिबाउंड भारत की निरंतर आर्थिक सुधार के लिए उज्ज्वल संभावनाएं प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार और आरबीआई की अडिग प्रतिबद्धता के साथ, भारत 2021-22 की अगली तीन तिमाहियों में और भी तेजी से ठीक होने की ओर अग्रसर है। तेजी से बढ़ते टीकाकरण कवरेज और महामारी प्रबंधन के साथ समृद्ध अनुभव यह विश्वास प्रदान करते हैं कि तीसरी लहर की स्थिति में भी वसूली जारी रखी जा सकती है।

वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) के अनुसार शहरी क्षेत्रों के लिए 9 सितंबर 2021 को जारी अक्टूबर-दिसंबर 2020 की अवधि के लिए पीएलएफएस के नवीनतम तिमाही बुलेटिन के अनुसार, श्रम बल भागीदारी दर, यानी श्रम की आपूर्ति, जुलाई-सितंबर में 37.0% से अक्टूबर-दिसंबर 2020 में 37.3%; बढ़ी है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात, यानी कार्यरत श्रम बल, जुलाई-सितंबर 2020 में 32.1% से बढ़कर अक्टूबर-दिसंबर 2020 में 33.5% हो गया, जबकि इसी अवधि में बेरोजगारी दर 13.3% से घटकर 10.3% हो गई। क्षेत्र-वार वृद्धि दर अनुबंध में तालिका में दी गई है।

2. अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम

(i) 2018-19 और 2021-22 के केंद्रीय बजट घोषणाओं के अनुसरण में, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 28 सितंबर 2021 को आयोजित अपनी बोर्ड बैठक में गोल्ड स्पॉट एक्सचेंजों की स्थापना के लिए एक रूपरेखा को अंतिम रूप दिया है। गोल्ड स्पॉट ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद (ईजीआर) के व्यापार के रूप में माना जाता है, जो सेबी के साथ पंजीकृत तिजोरियों में जमा किए गए भौतिक सोने के

एवज में जारी एक "सुरक्षा" होगी और सेबी पंजीकृत डिपॉजिटरी के साथ डीमैट रूप में होगी। सेबी अपने प्रस्तावित सेबी (वॉल्ट मैनेजर्स) विनियम, 2021 के माध्यम से सोने की तिजोरियों को भी विनियमित करेगा। गोल्ड एक्सचेंज भारत में अंतर्निहित मानकीकृत सोने के साथ ईजीआर खरीदने और बेचने के लिए एक राष्ट्रीय मंच होगा और निवेश तरलता, सोने की गुणवत्ता में आश्वासन आदि जैसे लाभों के साथ सोने के लिए एक कुशल और पारदर्शी राष्ट्रीय मूल्य संरचना भी तैयार करेगा।

(ii) गिफ्ट-आईएफएससी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टीईसी-सिटी-इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर) में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, सरकार ने तीन वर्षों में 45.75 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ 'फिनटेक इंसेंटिव स्कीम' को मंजूरी दी है। इस योजना में आईएफएससी में स्थित फिनटेक स्टार्ट-अप को उनके जीवन-चक्र में विभिन्न चरणों जैसे कि विचार, ऊष्मायन, अवधारणा का प्रमाण, व्यावसायीकरण और अप स्केलिंग के माध्यम से समर्थन देने के लिए अनुकूलित प्रोत्साहन की परिकल्पना की गई है।

(iii) सचिव (आर्थिक कार्य) ने 23 सितंबर, 2021 को रेल मंत्रालय, सड़क, राजमार्ग और परिवहन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, गृह मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ केपेक्स परिव्यय, व्यय और मासिक लक्ष्यों की समीक्षा की थी।

(iv) भारत सरकार के एक समन्वित और उत्तरदायी भारतीय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली कार्यक्रम सृजित करते हुए (सीसीआरआईएसपी) वित्तपोषण के लिए एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) के साथ 10 सितंबर, 2021 को 500 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(v) भारत सरकार और एडीबी के बीच झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के एक ऋण समझौते पर 8 सितंबर, 2021 को 112 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के लिए हस्ताक्षर किए गए थे।

(vi) महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए 300 मिलियन अमरीकी डालर ऋण (ओसीआर) के अतिरिक्त वित्तपोषण पर एडीबी के साथ 8 सितंबर, 2021 को हस्ताक्षर किए गए थे।

(vii) निम्न के लिए ऋण वार्ता:

क. 4.5 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के लिए 14 सितंबर, 2021 को आइजोल सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट आयोजित किया गया था।

ख. 61 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के लिए 16 सितंबर, 2021 को अगरतला शहर शहरी विकास परियोजना शुरू की गई थी।

(viii) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन, (एसपीएमसीआईएल) द्वारा ढाले गए सभी विषयों के स्मारक सिक्के की विदेशी बिक्री के लिए अनुमोदन के संबंध में एसपीएमसीआईएल को अवगत करा दिया गया है।

3. सितंबर, 2021 के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गईं: